

177

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० 437/2011/07(120)/XXVII(8)/2009

दिनांक:: देहरादून :: 28 मार्च, 2011

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 4-क की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उ०प्र० अधिनियम संख्या 01 वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके शासन द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 118/प०अ०/2004-328 पर्य०/2002 दिनांक 03-03-2004 एवं अधिसूचना सं० 337/2010/7(120)/XXVII(8)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 के क्रम में नयी पर्यटन इकाई को सुख-साधन कर में दी जाने वाली छूट को स्पष्ट करने के उद्देश्य से इस अधिसूचना को निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) ऐसी पर्यटन इकाई, जो नयी भूमि पर नये निर्माण के उपरान्त स्थापित हुई हैं, को व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथि अथवा उक्त विज्ञप्तियों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार अनुमन्य तिथि से 5 वर्ष तक सुख-साधन कर की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) ऐसी इकाइयाँ, जिनके द्वारा जमीन/भवन का क्रय करके उसको सम्पूर्ण रूप से परिवर्तित कर व्यवसायिक उपयोग के लिये पर्यटन इकाई के रूप में निर्मित किया गया है तथा अपनी वर्तमान भूमि/भवन के बाजार मूल्य के सापेक्ष कम से कम 50 प्रतिशत का अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया हो ऐसी इकाई को भी व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि अथवा विज्ञप्तियों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार अनुमन्य तिथि से 5 वर्ष के लिये सुख-साधन कर में छूट अनुमन्य होगी बशर्ते इस स्थान पर पूर्व में सुख-साधन कर की छूट का लाभ न लिया गया हो।

(ग) ऐसी पुरानी इकाइयाँ जो अपने वर्तमान बाजार मूल्य के सापेक्ष कम से कम 25 प्रतिशत का अतिरिक्त पूंजी निवेश करके पुरानी इकाई का विस्तार करती हैं उन्हें विस्तारित सीमा तक विस्तार के उपरान्त व्यापार प्रारम्भ करने अथवा विज्ञप्तियों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार अनुमन्य तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये सुख-साधन कर में छूट अनुमन्य होगी बशर्ते कि पुरानी इकाई द्वारा उस विस्तारित स्थान पर पूर्व में सुख-साधन कर की छूट का लाभ नहीं लिया गया हो। इकाई के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में वही दिशा-निर्देश लागू होंगे जो कि केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये औद्योगिक पैकेज एवं व्यापार कर व्यवस्था में नयी इकाई के सम्बन्ध में व्यापार कर अधिनियम की धारा-4(क) के अन्तर्गत लागू थे।

(घ) नवीकरण एवं विस्तारीकरण के मामलों में निर्णय सुख-साधन कर कमिशनर की अध्यक्षता में उनके द्वारा गठित समिति द्वारा लिया जायेगा जिसमें उद्योग एवं पर्यटन विभाग के नामित प्रतिभागी भी सम्मिलित होंगे।

(ङ) सुख साधन कर की छूट विस्तारीकरण के मामलों को छोड़कर एक स्थान पर केवल एक बार ही अनुमन्य होगी।

(च) ऐसे मामले जिनमें पूर्व में सुख-साधन कर की छूट ली जाती रही है और उनके नयी पर्यटन इकाई होने में कोई संशय नहीं है उन्हें केवल इस आधार पर छूट से वंचित नहीं किया जायेगा कि उन्होंने छूट के लिये पूर्व में पर्यटन विभाग/दिनांक 08-12-2009 के बाद वाणिज्य कर विभाग में आवेदन नहीं किया है। ऐसे मामलों का कमिशनर सुख-साधन कर के स्तर से परीक्षण किया जायेगा और सम्बन्धित इकाई के अभिलेखों से जांचोपरान्त इनका विनियमितिकरण किया जायेगा। भविष्य में भी सुख-साधन कर की छूट हेतु नई पर्यटन इकाई द्वारा कमिशनर सुख-साधन कर को आवेदन दिया जायेगा जिनके स्तर से परीक्षणोपरान्त आदेश निर्गत किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० 432 / 2011 / 07(120) / XXVII(8) / 2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की, जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाइल हेतु / एन०आई०सी०।

आज्ञा से,
(सी०एस०समवाल)
अपर सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification NO. 432/2011 /07 (120)/ XXVII(8)/2009 dated 28 March, 2011 for general information.

Uttarakhand Shasan
VITTA ANUBHAG-8
NO. 432/2011 /07 (120)/ XXVII(8)/2009
Dehradun :: Dated: 28 March, 2011

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4A of the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975 (as applicable to the State of Uttarakhand) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor, with a view to clarify the exemption to be given in Luxury Tax to the new Tourism Units, is pleased to issue in continuation of notification no. 118/ Pary. Anu./ 2004-328 Pary/ 2002 dated March 03, 2004 and notification no. 337/2010/07(120)/ XXVII(8)/ 2009 dated March 31, 2010, this notification:-

(a) Such tourism unit as has been established after new construction on new land shall be allowed exemption in luxury tax for 5 years from the date of commencement of business or from the date allowed in the conditions specified in the above notifications issued by the Government.

(b) Such units as have after purchasing land/ building completely renovated and constructed it as a tourism unit for commercial purpose and have made additional investment of at least 50 percent of the current market value of the present land/ building shall also be allowed exemption in luxury tax for 5 years with effect from the date of commencement of business or from the date allowed in the conditions specified in the above notifications issued by the Government, provided the benefit of the exemption in luxury tax for this place has not been availed previously. .

(c) Such old units as undertake expansion after making additional investment of at least 25 percent vis-a-vis their current market value shall be allowed exemption in luxury tax to the extent of expansion for 5 years with effect from the date of commencement of business or from the date allowed in the conditions specified in the above notifications issued by the Government, provided the benefit of the exemption in luxury tax for the expanded place has not been availed previously. In

the case of expansion of a new unit the same rules and procedures shall apply as are prescribed in the industrial package given by the Central Government and as were in force under section 4(A) of the Trade Tax Act under the Trade Tax System in relation to the new units.

(d) In cases of renovation and expansion decisions shall be taken by the Committee Constituted under the Chairmanship of the Commissioner Luxury Tax wherein nominated members of the Industry and Tourism Department shall also be included.

(e) Exemption in luxury tax shall be allowed only once at one place except in cases of expansion.

(f) In such cases, where exemption in luxury tax was being availed previously and there is no doubt in their being new tourism units they shall not be deprived of the exemption only on the ground that they have not applied for exemption previously to the tourism department/ after 08-12-2009 to the Commercial Tax Department. Such cases shall be examined by the Commissioner Luxury Tax and after examining the records of the units shall be regularised. In future also for exemption of luxury tax application shall be made to the Commissioner Luxury Tax from whose level after examination orders shall be issued.



(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.